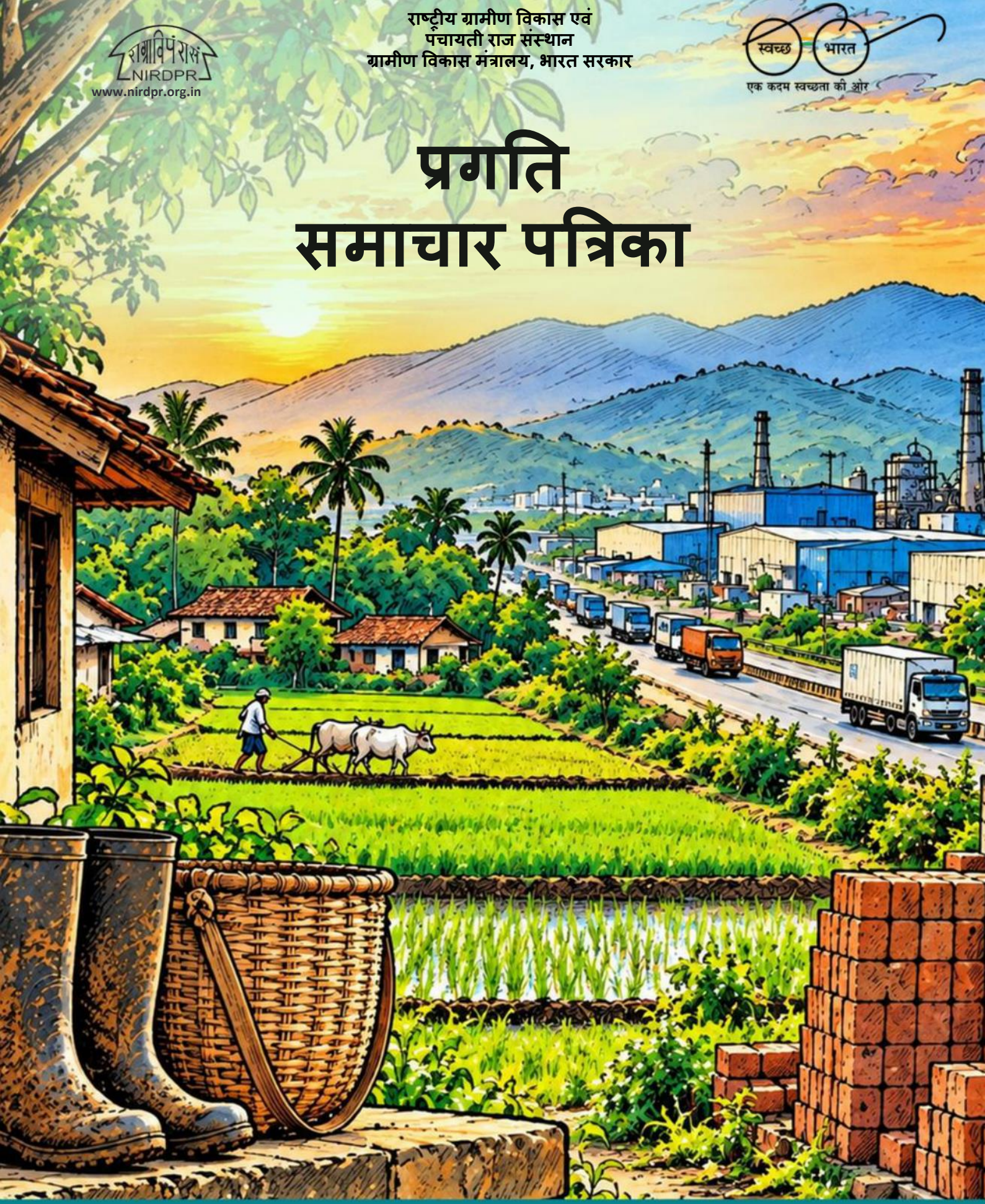
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राग्रावि पं रासं
NIRDPR
www.nirdpr.org.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रगति
समाचार पत्रिका



जहाँ खेत और कारखाने मिलते हैं | दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच तांबाटी का सफर

अक 375 अगस्त 2026

इस अंक में...

आवरण कथा | जहाँ खेत और कारखाने मिलते हैं: दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच तांबाटी का सफर -4

1. सुश्री रोहिणी भाजिभाकरे, आईएएस, ने एनआईआरडीपीआर के उप महानिदेशक का पदभार सँभाला - 9
2. डीएवाई-एनआरएलएम के तहत संस्थागत तंत्र और लैंगिक मैदानी अध्ययन स्थलों के विकास पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण - 10
3. केरल एसआरएलएम के अधिकारियों के लिए एनआईआरडीपीआर का 'कौशल प्रवेश' प्रशिक्षण -12
4. शहरी शासन में क्षमता निर्माण से भारत-नेपाल सहयोग को मजबूती -13
5. एसएचजी और सीआरपी के लिए हर्बल सौंदर्य प्रसाधन बनाने का प्रशिक्षण -14
6. अरुणाचल प्रदेश एसआरएलएम के सीआरपी-ईपी के लिए गैर-कृषि विपणन कौशल पर प्रारंभिक प्रशिक्षक प्रशिक्षण, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी -16
7. एक माह के सामाजिक अंकेक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण - 18
8. हिमाचल प्रदेश के मास्टर सीआरपी के लिए टिकाऊ पशुपालन का प्रशिक्षण -19
9. एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी में एसएचजी उत्पादों के निर्यात विपणन पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण - 20
10. पीजीडीआरडीएम और आरएम के विद्यार्थियों ने परिसर स्वच्छता अभियान में भाग लिया - 23
11. पर्यावरण संरक्षण के लिए एनआईआरडीपीआर का सामुदायिक पौधरोपण अभियान - 24
12. एनआईआरडीपीआर में बीडीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम - 26
13. डीएवाई-एनआरएलएम के तहत सामाजिक समावेशन को गति देने पर राष्ट्रीय कार्यशाला - 27

15. सामाजिक जवाबदेही और सामाजिक अंकेक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण सामग्री पर लेखन कार्यशाला - 29

16. एनआरएलएम प्रकरण अध्ययन शृंखला | बंद करघे से जीवंत विरासत तक: गोवा के शिरोडा में कुणबी साड़ी के पुनरुद्धार से नई आजीविकाएँ -30

17. डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला उद्यमों के वित्तपोषण को बढ़ावा -33

18. एनआरएलएम प्रकरण अध्ययन शृंखला | रुचि से समृद्धि तक: गृहिणी से लखपति दीदी बनीं सुमे शर्मा -34

19. एनआईआरडीपीआर में 80वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह -36

20. अकेले आगे बढ़कर बदलाव लाने वाली ग्राम प्रधान शोभा देवी - 37

21. विद्यार्थी मंच | वन के रक्षक: ओडिशा के साझा संसाधनों की रक्षा करते समुदाय - 40

22. एनआईआरडीपीआर में पीजीडीआरडीएम और पीजीडीएम (आरएम) के नए बैचों का स्वागत - 42

जहाँ खेत और कारखाने मिलते हैं
दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच तांबाटी का सफर

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नगर-सीमांत गाँव तांबाटी में 26 दिन के मैदानी प्रवास के अनुभव

सुश्री आराधना महतो
पीजीडीएम–आरएम, एनआईआरडीपीआर
aradhana.mahato.in@gmail.com



तांबाटी में पहली सुबह दो आवाजों के साथ होती है। पहली है बचे हुए साझा चरागाह की ओर जाते मवेशियों की जानी-पहचानी धीमी आहट। दूसरी है मुंबई–पुणे गलियारे से खोपोली–खालापुर के औद्योगिक क्षेत्रों की ओर मुड़ते ट्रकों की लगातार गूँज। इन दो ध्वनियों के बीच 1,706 निवासियों और 407 परिवारों का यह गाँव कृषि-प्रधान पहचान से नगर-सीमांत पहचान की ओर बढ़ रहा है। किसी ग्रामीण समुदाय के लिए यह बड़ा बदलाव है।

छब्बीस दिनों तक मैंने इस बदलाव को करीब से देखा। एक घर के बाहर साथ रखे कीचड़ सने जूते, बाँस की टोकरी और ताजी ईंटों की दीवार का दृश्य मेरे मन में रह गया। जूते खेत के थे, ईंटें कारखाने की। दोनों एक ही परिवार की जिंदगी का हिस्सा थे।

दो अर्थव्यवस्थाओं के संगम पर एक गाँव

तांबाटी खालापुर तालुका में, रायगढ़ जिले में है। यह गाँव खोपोली से करीब 20–25 किलोमीटर दूर मुंबई–पुणे गलियारे के औद्योगिक क्षेत्र में है। प्रशासनिक रूप से यह ग्राम पंचायत है। यहाँ प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का औद्योगिक क्षेत्र किसी खेतीहर बस्ती की सीमा तक पहुँचता है तो क्या बदलता है।

विकास भूगोलवेत्ता टेरी मैक्गी ने ऐसे क्षेत्रों के लिए 'देसाकोटा' शब्द दिया। बहासा भाषा में 'देसा' का अर्थ गाँव और 'कोटा' का अर्थ शहर है। ऐसे क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे में घुलती हैं। सेसिलिया टाकोली ने इसी विचार को ग्रामीण–शहरी सातत्य के रूप में आगे बढ़ाया। उनके अनुसार नगर-सीमांत क्षेत्रों की अपनी आर्थिक व्यवस्था, गति और कमजोरियाँ हैं। तांबाटी इसका सटीक उदाहरण है। लगभग 40 प्रतिशत भूमि पर धान, आलू, टमाटर, बैंगन, पत्तेदार सब्जियाँ, दालें और छोटे मोटे अनाज उगते हैं। करीब 15 प्रतिशत भूमि साझा संपत्ति है। शेष भूमि धीरे-धीरे आवासीय भूखंडों, छोटे कारखानों और माल ढुलाई केंद्रों में बदल रही है। खेती के लगभग एक चौथाई क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित है। शेष 85 प्रतिशत क्षेत्र मानसून पर निर्भर है। मुझे गाँव में कहीं ठहराव महसूस नहीं हुआ। उद्योगों की निकटता ने यहाँ के लोगों को नए काम दिए हैं।

टिकाऊ आजीविका के दृष्टिकोण से तांबाटी

अपने अनुभवों को समझने के लिए मेरे लिए सबसे उपयोगी रहा रॉबर्ट चैंबर्स और गॉर्डन कॉनवे का

विकसित किया हुआ टिकाऊ आजीविका ढाँचा, जिसे बाद में डीएफआईडी ने औपचारिक रूप दिया। इसमें परिवार की प्राकृतिक, भौतिक, वित्तीय, मानवीय और सामाजिक पूँजी देखी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन-सी बढ़ रही है और कौन-सी घट रही है।



तांबाटी की प्राकृतिक पूँजी दबाव में है। कृषि भूमि सिकुड़ रही है, बढ़ते बोरवेल से भूजल स्तर गिर रहा है, साझा चरागाह अनुमानतः 40 से 50 प्रतिशत घट चुके हैं और लगातार खेती से मिट्टी थक रही है। भौतिक पूँजी बढ़ रही है। लगभग सभी घरों में बिजली और मोबाइल संपर्क है, राज्य राजमार्ग तक पक्की सड़क है और करीब 80 प्रतिशत घरों में शौचालय हैं। कारखाने की मजदूरी, एसएचजी ऋण, पीएम-किसान की राशि, मनरेगा के कार्यदिवस और पीडीएस का अनाज वित्तीय साधनों को विविध बनाते हैं। 84.8 प्रतिशत साक्षरता, 74.36 प्रतिशत महिला साक्षरता और ऊँचे विद्यालय नामांकन से मानवीय पूँजी बढ़ रही है। बारह वर्ष की बच्ची भी अपने लिए नई संभावनाएँ देख पा रही है। पाँचवीं और शायद सबसे प्रभावशाली सामाजिक पूँजी एसएचजी, पंचायत और रिश्तेदारी के उन रोजमर्रा के संबंधों में बसती है जो सरकारी सहायता की पहुँच से बाहर के झटकों को भी सह लेते हैं।

इस दृष्टि से गाँव की कहानी में एक पूँजी की कमी दूसरी पूँजी पूरी करती है। साझा भूमि घटी तो वित्तीय और सामाजिक पूँजी बढ़ी। कृषि आय अनिश्चित हुई तो औद्योगिक मजदूरी और एसएचजी ऋण ने सहारा दिया। ग्रामीण विकास योजनाएँ इस बदलाव को सँभालने में मदद करती हैं।

"प्राकृतिक पूँजी घटे तो गाँव तभी टिकता है जब मानवीय और सामाजिक पूँजी उसकी भरपाई के लिए बढ़े।"

ग्रामीण विकास योजनाएँ रोजमर्रा का जीवन कैसे बदल रही हैं

किसी भी परिवार में जाएँ तो योजनाओं का असर एक साथ दिखता है। जैसे कारखाने की लंबी पाली के लिए परिवार स्टील के टिफिन के डिब्बे एक-दूसरे पर जमाता है, वैसे ही योजनाएँ एक-दूसरे का सहारा बनती हैं।

मनरेगा करीब 60 प्रतिशत पात्र परिवारों तक पहुँचता है। भुगतान में देरी चिंता का विषय है, फिर भी रोजगार की गारंटी खेती के मंद महीनों में भूमिहीन और सीमांत परिवारों को संभालती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग हर घर तक पहुँचती है। मासिक राशन से कई परिवार अपने बच्चे को निर्माण स्थल भेजने के बजाय स्कूल भेज पाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम-किसान, आयुष्मान भारत, मध्याह्न भोजन, टीकाकरण अभियान और आईसीडीएस का योगदान किसी न किसी परिवार की कहानी में दिखता है। राशन कार्ड, आधार और आयुष्मान कार्ड उसी स्टील की अलमारी में रखे हैं जिसमें कारखाने का पहचानपत्र है।

सबसे उल्लेखनीय बदलाव महिलाओं के जीवन में है। तांबाटी में बीस से अधिक सक्रिय स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण

आजीविका मिशन के तहत काम करते हैं। इनसे गाँव की अनुमानतः 40 से 50 प्रतिशत महिलाएँ जुड़ी हैं। अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार विकास का अर्थ लोगों की वास्तविक स्वतंत्रताओं और क्षमताओं का विस्तार है। तांबाटी के एक एसएचजी की बैठक में इस विचार को मैंने किसी पाठ्यपुस्तक से अधिक स्पष्टता से समझा।

रजिस्टर में बचत के अलावा ऋण पर खरीदी सिलाई मशीन, घर का सिलाई काम बढ़ाने के लिए एक युवा माँ का ढाई लाख रुपये का ऋण, बेटी की कोचिंग पर चर्चा और साप्ताहिक हाट के लिए सब्जियों का साझा ऑर्डर दर्ज था। एनआरएलएम से वित्तीय पहुँच बढ़ी और साथ ही नई संभावनाएँ खुलीं।

तांबाटी में महिला साक्षरता 74.36 प्रतिशत है और उपसरपंच महिला हैं।

आँकड़े कागज पर हैं और क्षमता व्यवहार में दिखती है।

बाँस की टोकरी और खेती की भूमिका

बाहर से देखने पर खेती का महत्व कम लग सकता है। राजेश गणेश दलवी के पास दस भैंसें हैं और वे अपनी जमीन जोतते हैं। खेती और डेयरी मिलाकर उनके परिवार को हर महीने ₹35,000 से ₹45,000 मिलते हैं। छोटे और सीमांत किसान आज भी खोपोली के बाजारों और स्थानीय संग्रह केंद्रों तक आलू, पत्तेदार सब्जियाँ और रोज का दूध पहुँचाते हैं। अधिकतर पशुधन महिलाएँ संभालती हैं। मौसम बदलने पर भी रसोई बगीचे और छोटे बाग भोजन में विविधता बनाए रखते हैं।

आजीविका के विविधीकरण पर फ्रैंक एलिस के अध्ययन बताते हैं कि विकासशील देशों में ग्रामीण परिवार जोखिम सँभालने के लिए खेती, खेती से जुड़े अन्य काम और गैर-कृषि गतिविधियाँ साथ करते हैं। तांबाटी इसका जीवंत उदाहरण है। किसान नई चीजें अपनाने को उत्सुक थे। प्रवास के दौरान मैंने गोबर, सूखी पत्तियों और रसोई के कचरे से कम लागत वाली जैविक खाद बनाने का व्यावहारिक प्रदर्शन आयोजित करने में मदद की। हमारी दादियाँ पहले से यह तरीका जानती थीं। बढ़ते दामों पर यूरिया और डीएपी खरीद रहे किसानों ने उसी शाम पूछा कि खाद कब तैयार होगी और क्या घर के पीछे छोटे गड्ढों में बनाई जा सकती है। कम लागत वाली, जलवायु के अनुकूल खेती में उनकी रुचि पहले से है। उसे थोड़ा सहयोग चाहिए।

जूते और ईंटें: कारखाने से मिला सहारा

औद्योगिक क्षेत्र ने तांबाटी की खेती को सहारा दिया है। पास के एमआईडीसी क्षेत्र में करीब 26 कार्यदिवस के लिए महीने में लगभग ₹10,000 से ₹15,000 मिलते हैं। साफ-सफाई और कुशल काम में यह राशि ₹30,000 तक है। कई परिवारों में पति की नियमित मजदूरी और पत्नी की सिलाई या एसएचजी उद्यम की आय मिलकर खराब मानसून का झटका सहने में मदद करती हैं। इसी कारण ली और टोडारो का प्रवासन का धकेल-खींच मॉडल यहाँ आंशिक रूप से लागू होता है। खोपोली के उद्योग रोजगार देते हैं और दैनिक आवाजाही की दूरी पर हैं। इसलिए लोग दूर पलायन करने के बजाय काम पर जाकर घर लौटते हैं। गाँव के लोग गाँव में ही रह पाते हैं। यह नीति की एक शांत सफलता है।



वेदिका वाल्सो से मैं उनके घर के सामने वाले कमरे में मिली, जहाँ वे पालियों के बीच कुर्ते सिल रही थीं। पति पास की इकाई में साफ-सफाई का काम करते हैं। उनकी सिलाई मशीन एसएचजी से मिले ऋण से खरीदी गई। दोनों मिलकर महीने में ₹15,000 कमाते हैं और ₹2.5 लाख का ऋण चुका पा रहे हैं। उनकी बातों में अपने फैसले लेने का आत्मविश्वास था। एनआरएलएम का ऋण, साइकिल से पहुँचने योग्य कारखाना और पंचायत की पक्की सड़क मिलकर इस विकल्प को संभव बनाते हैं।

साझा संसाधन और ऑस्ट्रम का प्रश्न

तांबाटी के साझा चरागाह, मौसमी नाले और तालाब एक पीढ़ी में अनुमानतः 40 से 50 प्रतिशत घटे हैं। उनकी जगह उद्योग और आवास आए हैं। एलिनॉर ऑस्ट्रम के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित शोध 'साझा संसाधनों का शासन' ने बताया कि समुदाय आठ सिद्धांतों के आधार पर संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन कर सकते हैं। इनमें स्पष्ट सीमाएँ, सामूहिक नियम, निगरानी और स्थानीय स्तर पर उल्लंघन के अनुरूप दंड शामिल हैं। तांबाटी में इनके लिए आधार मौजूद है -पंचायत सक्रिय है, बारी-बारी से चराई के अनौपचारिक नियम हैं और तालाबों की देखभाल की परंपरा जीवित है। औद्योगिक दबाव पर गाँव के नियम लागू नहीं होते। पंचायत के साथ बनाई सामुदायिक कार्ययोजना इसलिए साझा संसाधनों के स्थानीय प्रबंधन, तालाबों से गाद निकालने और पुनर्भरण, क्रमिक चराई के औपचारिक नियम और पास के औद्योगिक क्षेत्रों के साथ शिकायत निवारण तंत्र पर जोर देती है। तांबाटी में औद्योगीकरण के साथ साझा संसाधन तभी बचेंगे जब नियम बनाने में गाँव की भी भूमिका होगी।

ऐसा शासन जिसके दरवाजे खुले हैं



तांबाटी की ग्राम पंचायत में लोग बिना समय लिए पहुँच जाते हैं। पंचायत सचिव और महिला उपसरपंच के नेतृत्व में पंचायत भूमि अभिलेख, कल्याणकारी लाभों का वितरण, पीडीएस की निगरानी, जलापूर्ति और विवाद सँभालती है। आरक्षित सीटों ने महिलाओं और वंचित समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में स्थान दिया है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) हर वर्ष बनती है।

रॉबर्ट पुटनम ने सामाजिक पूँजी के दो रूप बताए। एक समूह के अंदर संबंध मजबूत करती है और दूसरी अलग-अलग समूहों को जोड़ती है। तांबाटी में एसएचजी, रिश्तेदारी के नेटवर्क, सामुदायिक

उत्सवों और श्रम बाँटने की परंपरा के रूप में पहली तरह की पूँजी प्रचुर है। पंचायत अब महिला एसएचजी और संबंधित सरकारी विभागों, किसानों और नगर-सीमांत बाजारों, तथा पंचायत और उद्योगों की सीएसआर पहलों के बीच संबंध बना रही है। एनसीसी और पंचायत का संयुक्त स्वच्छता अभियान उसी संस्थागत समन्वय का छोटा अभ्यास था जिसकी तांबाटी को बड़े पैमाने पर जरूरत होगी।

सर्वेक्षण से आगे एक संवाद

मैदानी प्रवास के कुछ यादगार क्षण अनियोजित थे। एसएचजी की महिलाओं के साथ सहभागी खेलों के लिए तय चालीस मिनट की गतिविधि लगभग दो घंटे चली। महिलाएँ हँसीं, बहस की, एक-दूसरे के नेतृत्व के अंदाज पर चुटकी ली और फिर खुद अपनी प्राथमिकताएँ बताने लगीं। सब्जियों के लिए साझा शीतगृह, कारखानों की वर्दी के ऑर्डर लेने योग्य सिलाई समूह और बेटियों के लिए डिजिटल साक्षरता की कक्षा। रॉबर्ट चैंबर्स का 'सबसे पीछे वालों को पहले रखना' और सहभागी ग्रामीण आकलन का मतलब यही था। इसमें शोधकर्ता की कलम समुदाय के हाथ में आ जाती है। उस कमरे में मैंने जाना कि तांबाटी के एसएचजी वित्तीय समूह से आगे बढ़कर गाँव में भरोसे के साथ योजना बनाने वाली संस्था बन रहे हैं।

"जब महिलाओं ने पूछे जाने की प्रतीक्षा छोड़कर खुद सवाल उठाने शुरू किए, उसी क्षण अध्ययन ने अपना रूप ले लिया।"

योजनाएँ व्यवहार में क्या कर रही हैं

तांबाटी में ग्रामीण विकास बजट की मदों के बजाय धीरे-धीरे खड़ा होता एक सहारा दिखता है। लेव वायगोत्स्की ने शिक्षा में ऐसे सहारे का वर्णन किया था जो सीखने वाले को स्वयं अगला कदम उठाने लायक बनाता है। योजनाएँ गाँव के साथ इसी तरह खड़ी होती हैं।

मनरेगा फसलों के बीच परिवारों को समय देता है। पीडीएस महँगे भोजन से शिक्षा खर्च को बचाता है। पीएमएवाई से कच्ची दीवारें पक्की हुईं। स्वच्छ भारत से लगभग पाँच में चार घरों में शौचालय बने। एनआरएलएम महिलाओं की बचत को कार्यशील पूँजी में बदल रहा है। पीएमकेवीवाई और डीडीयू-जीकेवाई से युवा उन्हीं कारखानों में साफ-सफाई से तकनीकी भूमिकाओं तक जा सकते हैं। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य उपकेंद्र के चलते परिवार को अस्पताल का बिल चुकाने के लिए भैंस नहीं बेचनी पड़ती। पीएम-किसान से छोटी लेकिन नियमित राशि किसान के खाते में आती है। मध्याह्न भोजन बच्चों को स्कूल में टिकाए रखता है, ताकि वे कारखाने की पाली के आगे भी जीवन की कल्पना कर सकें।

हर योजना की अपनी भूमिका है। साथ मिलकर ये योजनाएँ नगर-सीमांत गाँव को अपनी शर्तों पर भविष्य तय करने का आधार देती हैं। सेन की भाषा में यही कल्याण और स्वतंत्रता का अंतर है।

तांबाटी ने मुझे क्या सिखाया

मैं ग्रामीण प्रबंधन की छात्रा के रूप में तांबाटी आई थी। लौटते समय मेरी समझ सरल हो गई थी। गाँव उपलब्ध साधनों से खुद अपना विकास करता है। ग्रामीण विकास योजनाएँ उसे काम करने के औजार देती हैं।

योजनाएँ औजार हैं, पंचायत कार्यस्थल है, एसएचजी काम करने वाले हाथ हैं और कारखाना क्षितिज पर है। तांबाटी अपनी लय में विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों में जूते

सुश्री रोहिणी भाजिभाकरे, आईएएस, ने एनआईआरडीपीआर के उप महानिदेशक का पदभार संभाला



सुश्री रोहिणी भाजिभाकरे, आईएएस, ने एनआईआरडीपीआर के उप महानिदेशक का पदभार 4 अगस्त 2026 को संभाला। लोक प्रशासन में 18 वर्ष से अधिक के अनुभव के साथ वे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और ग्रामीण भारत के टिकाऊ और समावेशी विकास की नीतियाँ बनाने में योगदान देती हैं।

सुश्री रोहिणी ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और तमिलनाडु में विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। इनमें कानून-व्यवस्था, शहरी और ग्रामीण विकास, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल विकास, बुनियादी ढाँचा, शासन, कृषि और जलवायु कार्रवाई शामिल हैं।

सुश्री रोहिणी शासन में जनकेंद्रित और नवाचारी दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं। वे नेशनल जियोग्राफिक की वृत्तचित्र फिल्म 'द ग्रेट इंडियन इलेक्शन' में दिखाई दीं। उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उनके नाम गिनीज विश्व रिकॉर्ड है और उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में चीवनिंग फेलोशिप प्राप्त की है।

कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियर सुश्री रोहिणी सेलम जिले के 227 वर्षों के इतिहास में पहली महिला जिला कलेक्टर बनीं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव से आईं सुश्री रोहिणी छह भाषाएँ बोलती हैं और समावेशी तथा प्रभावी लोक सेवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संस्थागत तंत्र और जेंडर मैदानी अध्ययन स्थलों के विकास पर प्रशिक्षक का प्रशिक्षण, डीएवाई-एनआरएलएम



प्रशिक्षक का प्रशिक्षण के प्रतिभागी और संसाधन व्यक्ति, प्रो. रवींद्र गावली, एनआईआरडीपीआर के साथ

जेंडर बदलाव की संस्थागत नींव

डीएवाई-एनआरएलएम में जेंडर समानता को मुख्यधारा में लाने के लिए जेंडर अवधारणाओं की जानकारी के साथ ऐसी सक्रिय संस्थाओं, सक्षम कार्यकर्ताओं और व्यवस्थित प्रक्रियाओं की जरूरत है जिनसे महिला समूह अपने जीवन से जुड़े मुद्दे पहचानें, उठाएँ और उन पर कार्रवाई करें। इसी उद्देश्य से एनआईआरडीपीआर के डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू) के सहयोग से 3 से 6 अगस्त 2026 को हैदराबाद में संस्थागत तंत्र और लैंगिक मैदानी अध्ययन स्थलों के विकास पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) के दो समानांतर बैच आयोजित किए। समझ और सुविधा के लिए एक बैच हिंदी तथा दूसरा अंग्रेजी में चला। 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 69 प्रतिभागी शामिल

कार्यक्रम डीएवाई-एनआरएलएम के तहत चार स्तरीय जेंडर क्षमता निर्माण शृंखला का दूसरा चरण था। इससे पहले 18-22 मई 2026 के प्रथम स्तरीय जेंडर मॉड्यूल प्रशिक्षक प्रशिक्षण में 17 राज्यों के 64 प्रतिभागियों ने बुनियादी अवधारणाएँ समझीं। अगस्त के प्रशिक्षण में संस्थागत ढाँचे, मुद्दा-आधारित कार्रवाई और जेंडर मैदानी अध्ययन स्थलों के विकास पर काम हुआ।

प्रशिक्षण में जेंडर संपर्क व्यक्ति (जीपीपी) और उनके समूह, ग्राम संगठन व संकुल स्तरीय संघ की सामाजिक कार्रवाई समिति (एसएसी), पंचायत और खंड स्तर के जेंडर मंच तथा जेंडर संसाधन केंद्र (जीआरसी) की भूमिकाएँ समझाई गईं। चर्चा हुई कि ये संस्थाएँ अधिकारों, पात्र लाभों और जेंडर हिंसा (जीबीवी) के मामलों में मिलकर कैसे काम करें।

प्रतिभागियों ने मई के प्रशिक्षण की सीख, उसके उपयोग, अच्छे अनुभवों और चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने बुनियादी जेंडर अवधारणाओं को दोहराया और सामाजिक समावेशन, व्यावहारिक जेंडर जरूरतों (पीजीएन), रणनीतिक जेंडर हितों (एसजीआई) और



प्रशिक्षक का प्रशिक्षण के एक सत्र में समूह चर्चा करते प्रतिभागी



संस्थागत तंत्र और मुद्दा-आधारित कार्रवाई पर प्रस्तुति देता एक समूह

डीएवाई–एनआरएलएम की जेंडर एकीकरण व्यवस्था पर काम किया। प्रकरण अध्ययन, भूमिका-अभिनय और सहभागी मानचित्रण से संस्थागत तंत्र, अधिकार, पात्र लाभ, सत्ता संबंध, लैंगिक हिंसा के मामलों पर कार्रवाई और जेंडर मंचों को मजबूत करने की रणनीतियाँ समझीं। मैदानी अध्ययन स्थलों को गहन, समयबद्ध और स्थानीय संदर्भ के अनुकूल प्रदर्शन मंच बनाने पर जोर रहा। इसके लिए सक्रिय संस्थागत तंत्र, क्षमता निर्माण, विभागीय समन्वय, जेंडर निधि, जीआरसी, मामला प्रबंधन और मापनीय संकेतकों पर चर्चा हुई। 'इक्वल एमआईएस' के व्यावहारिक सत्र में जेंडर आँकड़े, रिपोर्टिंग और निगरानी समझाई गई।

प्रशिक्षण ने सीख को सहभागी कार्रवाई, मजबूत संस्थाओं और समुदाय स्तर पर मापे जा सकने वाले बदलाव से जोड़ा।

प्रशिक्षण में मैदानी क्रियान्वयन पर विशेष जोर था। प्रतिभागियों ने देखा कि संस्थागत तंत्र, महिला समूह और जेंडर मंच मिलकर मुद्दों की पहचान, संबंधित सेवाओं तक पहुँच, विभागीय समन्वय और अधिकारों तथा जेंडर हिंसा पर सामूहिक कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। अध्ययन स्थलों पर काम से एसआरएलएम अधिकारियों और मास्टर प्रशिक्षकों को खंड स्तर पर स्थिति का विश्लेषण करने, लक्ष्य तय करने, क्षमता बढ़ाने और समन्वय व निगरानी करने के तरीके मिले। कार्यक्रम से जेंडर संस्थाओं के कामकाज में सुधार और मापनीय, टिकाऊ बदलाव के लिए मैदानी अध्ययन स्थलों का व्यवस्थित विकास अपेक्षित है।

आलेख तैयार किया: राजीव रंजन सिंह, मिशन कार्यपालक–एसआईएसडी,
डीएवाई–एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ

केरल एसआरएलएम के अधिकारियों के लिए एनआईआरडीपीआर का ‘कौशल प्रवेश’ प्रशिक्षण





डॉ. जे. एस. रेड्डी, स्कूल प्रमुख एवं प्रोफेसर, सीआईएआरडी और डीडीयू-जीकेवाई, ‘कौशल प्रवेश’ प्रशिक्षण के प्रतिभागियों के साथ

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के डीडीयू-जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ ने 4-6 अगस्त 2026 को केरल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के अधिकारियों के लिए ‘कौशल प्रवेश’ अभिमुखीकरण आयोजित किया। केरल की कुटुंबश्री के प्रायोजन में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों की संस्थागत क्षमता बढ़ाना था।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में कुटुंबश्री के मुख्य परिचालन अधिकारी (कौशल) और राज्य व जिला कार्यक्रम प्रबंधक शामिल हुए। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन की समझ बढ़ाई, अनुभव साझा किए और ग्रामीण युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास कार्यक्रम चलाने की संस्थागत तैयारी पर काम किया।

उद्घाटन सत्र में एनआईआरडीपीआर के निदेशक (निगरानी एवं मूल्यांकन) श्री सुधाकर रेड्डी ने स्वागत किया। एनआईआरडीपीआर के प्रोफेसर और डीडीयू-जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ के कार्यपालक निदेशक डॉ. जे. एस. रेड्डी ने उद्घाटन संबोधन में कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। उन्होंने सतत क्षमता निर्माण पर जोर दिया, जिससे गुणवत्तापूर्ण कौशल कार्यक्रम चलें और ग्रामीण युवाओं को टिकाऊ आजीविका मिले।

उद्योगोन्मुख कौशल विकास का मैदानी अनुभव

पहले दिन प्रतिभागियों ने शमशाबाद के जीएमआर कौशल विकास केंद्र का दौरा किया। अधिकारियों ने उद्योगोन्मुख कौशल प्रशिक्षण की पद्धतियाँ देखीं। विशेष ध्यान प्रशिक्षण की गुणवत्ता, रोजगार मिलने और नौकरी में बने रहने पर रहा।

दौरे में अधिकारियों ने जमीनी कामकाज देखा और ऐसे व्यावहारिक तरीके समझे जिन्हें डीडीयू-जीकेवाई के कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और प्रभाव बेहतर करने के लिए अपनाया जा सकता है।

कौशल विकास व्यवस्था को मजबूती

कौशल प्रवेश कार्यक्रम में केरल एसआरएलएम के कार्यकर्ताओं ने संवाद किया, अनुभव बाँटे और संस्थागत कामकाज सीखा। परिचय सत्रों और मैदानी अनुभव के मेल से कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण कौशल विकास को अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने पर बल दिया गया।

शहरी शासन में क्षमता निर्माण से भारत–नेपाल सहयोग को मजबूती



डॉ. एस. ज्योतिस, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीजीएस एवं डीई; डॉ. अंजन कुमार भंज, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी; श्री मनोज कुमार, प्रभारी कुलसचिव एवं निदेशक (प्रशासन), और श्री प्रणब कुमार घोष, प्रभारी सहायक कुलसचिव (ई), के साथ प्रशिक्षण के प्रतिनिधि

एनआईआरडीपीआर के डीडीयू–जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ ने नेपाल के चुनिंदा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए 3–12 अगस्त 2026 को शहरी शासन पर दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम भारत और नेपाल के निरंतर विकास सहयोग और घनिष्ठ संबंधों का हिस्सा था।

कोशी प्रांत के चार जिलों इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुंग और तेह्रथुम से महापौर, अध्यक्ष, कार्यवाहक महापौर और नगरपालिका सदस्य आए। प्रतिनिधियों ने भारत के अनुभवों से सीखा और शहरी शासन की अच्छी पद्धतियाँ समझीं और अपने स्थानीय संदर्भों के अनुरूप उपायों पर विचार किया।

भारत–नेपाल विकास सहयोग को मजबूती

उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्रालय के उप सचिव श्री साकेत राजा मुसिनीपल्ली ने भारत और नेपाल की मजबूत साझेदारी में विकास सहयोग को अहम बताया। उन्होंने मानव संसाधन विकास सहित क्षमता निर्माण का महत्व रेखांकित किया, विशेषकर कृषि, बागवानी और प्रतिनिधिमंडल की प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों में।

उन्होंने कहा कि अनुभवों और सीख के आदान-प्रदान से दोनों देशों को लाभ होगा। उन्होंने लक्षित प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों के जरिए सहयोग मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

सीपीजीएस एवं डीई, एनआईआरडीपीआर के प्रोफेसर डॉ. एस. ज्योतिस सत्यपालन ने विशेष संबोधन दिया। सीपीआरडीपी एवं एसएसडी के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. अंजन कुमार भंज ने कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य बताए तथा प्रतिनिधियों से उनकी अपेक्षाएँ पूछीं।

शहरी शासन की अच्छी पद्धतियों से सीख

प्रतिनिधियों ने शहरी शासन, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी), कृषि, बागवानी, सीवेज प्रबंधन, शहरी कचरा प्रबंधन, पारिस्थितिक पर्यटन, बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी में शहरी स्थानीय निकायों के अच्छे अनुभव जानने की इच्छा जताई।

डॉ. भंज ने बताया कि इन विषयों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि नवाचारी पद्धतियों और संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए हैदराबाद, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अध्ययन दौरे तय किए गए हैं।

प्रतिनिधियों ने इन अनुभवों से सीखने और उपयोगी पद्धतियों को अपने क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार अपनाने में रुचि दिखाई।

ज्ञान का आदान-प्रदान और स्थानीय समाधान

कार्यक्रम में अनुभव बाँटने, एक-दूसरे से सीखने और शहरी शासन की व्यावहारिक पद्धतियाँ देखने का अवसर मिला। भारतीय विशेषज्ञों और नेपाल के स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के संवाद से प्रभावी योजना, सेवा वितरण और टिकाऊ शहरी विकास की समझ बढ़ने की अपेक्षा है।

एनआईआरडीपीआर के कुलसचिव एवं निदेशक (प्रशासन) श्री के. मनोज कुमार ने शहरी शासन और बाहर के अध्ययन दौरों की प्रभावी योजना पर जोर दिया। सहायक कुलसचिव (टी) डॉ. प्रणब कुमार घोष ने भी उद्घाटन में भाग लिया और प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ दीं।

हर्बल सौंदर्य प्रसाधन बनाने का प्रशिक्षण एसएचजी और सीआरपी के लिए



व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रतिभागी, डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, कौशल एवं रोजगार के लिए नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईएटी एवं एसजे), के साथ

हर्बल सौंदर्य प्रसाधन बनाने का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के कौशल एवं रोजगार के लिए नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र ने लखपति दीदी पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के लिए यह कार्यक्रम 24–28 अगस्त 2026 को संस्थान के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में आयोजित किया।

औषधीय और सुगंधित जड़ी-बूटियों से हर्बल सौंदर्य प्रसाधन बनाने की जानकारी और व्यावहारिक कौशल दिए गए। उद्देश्य स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से आजीविका और उद्यम के अवसर विकसित करना था।

व्यावहारिक अभ्यास में प्रतिभागियों ने सीखा कि औषधीय और सुगंधित जड़ी-बूटियों से मूल्यवर्धित सौंदर्य प्रसाधन कैसे बनाए जाएँ। ग्रामीण महिलाओं और एसएचजी सदस्यों के लिए हर्बल उत्पाद आधारित लघु उद्यमों की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

यह लखपति दीदी पहल के तहत कौशल, उद्यमिता और टिकाऊ आजीविका बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। एसएचजी और सीआरपी को तकनीकी कौशल मिलने से आय बढ़ाने वाली गतिविधियाँ विकसित हो सकती हैं और महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यम मजबूत हो सकते हैं।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में प्रतिभागियों को उपयुक्त तकनीक, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यम के अनुकूल माहौल में सीखने का मौका मिला। पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संसाधनों को आजीविका के मौजूदा अवसरों से जोड़ने का महत्व बताया गया।

अरुणाचल प्रदेश एसआरएलएम के सीआरपी-ईपी के लिए गैर-कृषि विपणन कौशल पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी



गैर-कृषि विपणन कौशल पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण में अरुणाचल प्रदेश एसआरएलएम के सीआरपी-ईपी और संकाय सदस्य



गुवाहाटी के नेडफी हाट में प्रतिभागियों ने संचालन मॉडल और ग्रामीण उत्पादों के विपणन व संवर्धन की पद्धतियाँ सीखीं

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके परिवारों व समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। एसएचजी अनेक उत्पाद बनाते और बेचते हैं, लेकिन सीमित पैमाने से बाजार की पहुँच घटती है। ब्रांडिंग, उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग, मूल्य शृंखला, मूल्य निर्धारण, ई-विपणन, सामाजिक माध्यम, ग्राहक सेवा, संवाद और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण बाजार के अवसर बढ़ाता है। कर और जीएसटी नियमों की समझ तथा निरंतर मार्गदर्शन उद्यमों की वृद्धि और टिकाऊपन के लिए जरूरी हैं।

एनआईआरडीपीआर की दिल्ली शाखा के सीएमपीआरपीईडी ने अरुणाचल प्रदेश एसआरएलएम के सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों-उद्यम संवर्धन (सीआरपी-ईपी) के लिए 29 से 31 जुलाई 2026 तक गुवाहाटी के एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी में विपणन कौशल पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया। तीन दिवसीय आवासीय कार्यक्रम में 31 सीआरपी-ईपी शामिल हुए।

उद्देश्य सीआरपी-ईपी को मास्टर प्रशिक्षक बनाना था, ताकि वे ग्रामीण एसएचजी की महिला विपणन कौशल सिखाएँ। प्रशिक्षण में ब्रांडिंग, उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग, मूल्य शृंखला, मूल्य निर्धारण, बिक्री संवाद, ई-विपणन, सामाजिक माध्यम और कर व जीएसटी से जुड़ी चुनौतियाँ पहचानी गईं। प्रतिभागियों ने इन्हें हल करने और एसएचजी उद्यमों की बाजार पहुँच बढ़ाने के नए कौशल सीखे। अध्ययन दौरे और व्यावहारिक अभ्यास से प्रभावी विपणन पद्धतियाँ समझीं।

दिल्ली शाखा के सीएमपीआरपीईडी के सहायक निदेशक श्री चिरंजी लाल ने उद्घाटन किया। सत्रों और दौरों का संचालन एनआईआरडीपीआर के संकाय, राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तियों (एनआरपी) और अतिथि वक्ताओं ने किया। इनमें एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी के सहायक प्रोफेसर डॉ. एम. के. श्रीवास्तव और डॉ. रत्ना भुइयाँ, गुवाहाटी के एनआरपी श्री अश्विनी भट्टाचार्य, श्री चिरंजी लाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री आदर्श अग्रवाल, श्री सुधीर कुमार सिंह और दिल्ली शाखा के श्री सुरेश प्रसाद शामिल थे।

सत्रों के बाद 31 जुलाई 2026 को पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) के हाट का अध्ययन दौरा किया गया। प्रतिभागियों ने उसका संचालन मॉडल और अपनाई गई अच्छी पद्धतियाँ समझीं।

सीएमपीआरपीईडी के अधिकारियों ने ऑनलाइन प्रतिक्रिया सत्र के साथ प्रशिक्षण पूरा किया। प्रतिभागियों और वक्ताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।



एसएचजी उद्यमों की ब्रांडिंग, उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण और ई-विपणन पर कक्षा सत्र में सीआरपी-ईपी

एक माह के सामाजिक अंकेक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण



एलसीसी के लिए एक माह के सामाजिक अंकेक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक प्रशिक्षण में प्रतिभागियों और संसाधन व्यक्तियों का समूह चित्र

एनआईआरडीपीआर के सामाजिक अंकेक्षण केंद्र ने हैदराबाद के एनआईआरडीपीआर में 17–26 अगस्त 2026 को एलसीसी के लिए एक माह के सामाजिक अंकेक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किया गया। कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत हुआ।

प्रतिभागियों और संसाधन व्यक्तियों ने प्रस्तावित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए गहन क्षमता निर्माण किया। प्रशिक्षण में सामाजिक अंकेक्षण की समझ और पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाने की तैयारी पर बल दिया गया।

प्रशिक्षकों ने सामाजिक अंकेक्षण और सामाजिक जवाबदेही पर व्यवस्थित प्रशिक्षण देने की क्षमताएँ विकसित कीं। इस पहल से सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रियाओं और पद्धतियों को मजबूत करने वाले प्रशिक्षित कर्मियों का समूह तैयार होगा।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों और संसाधन व्यक्तियों ने बातचीत की, ज्ञान बाँटा और अनुभव साझा किए। इससे सीख समृद्ध होगी और प्रशिक्षक अपने संदर्भों में सामाजिक अंकेक्षण के व्यावहारिक पहलू समझ सकेंगे।

यह पहल व्यवस्थित क्षमता निर्माण से सामाजिक जवाबदेही, पारदर्शिता और सहभागी शासन मजबूत करने के एनआईआरडीपीआर के प्रयासों का हिस्सा है। सामाजिक अंकेक्षण केंद्र अधिक प्रभावी प्रक्रियाओं के लिए प्रशिक्षण और ज्ञान विकास में सहयोग देता रहा है।

प्रशिक्षक प्रशिक्षण से एलसीसी के एक माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को चलाने की संस्थागत क्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सामाजिक अंकेक्षण व जवाबदेही को सहयोग देने वाले प्रशिक्षित पेशेवरों का समूह विस्तृत होगा।

हिमाचल प्रदेश के मास्टर सीआरपी के लिए टिकाऊ पशुपालन पद्धतियों का प्रशिक्षण







डॉ. रवींद्र गावली, प्रोफेसर एवं स्कूल प्रमुख, एनआरएलएमआरसी, एनआईआरडीपीआर, और संसाधन प्रकोष्ठ के कर्मचारी टिकाऊ पशुपालन प्रशिक्षण के प्रतिभागियों के साथ एचपी-एसआरएलएम के मास्टर सीआरपी

टिकाऊ पशुपालन पर छह दिवसीय प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचपी-एसआरएलएम) के 25 मास्टर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के लिए 4-9 अगस्त 2026 को हैदराबाद में आयोजित किया गया। आयोजन एनआईआरडीपीआर के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संसाधन प्रकोष्ठ (एनआरएलएमआरसी) ने किया।

प्रतिभागियों ने घर के पिछवाड़े मुर्गीपालन, बकरीपालन और गोवंश प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी ली। जोर टिकाऊ और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पद्धतियों पर था। मास्टर सीआरपी इनसे ग्रामीण परिवारों को बेहतर पशुधन प्रबंधन अपनाने में मदद कर सकेंगे।

एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुर्गियों, बकरियों और गोवंश की पारंपरिक पशुचिकित्सा पद्धतियों का अभ्यास था। प्रतिभागियों ने स्थानीय पशु देखभाल के तरीके समझे और समुदाय में उनके इस्तेमाल पर विचार किया।

केवीके-सीआरआईडीए के मैदानी दौरे में प्रतिभागियों ने चारे की किस्में और टिकाऊ पशुधन प्रबंधन देखा। इस अनुभव ने कक्षा की तकनीकी जानकारी को जमीनी उपयोग से जोड़ा।

तकनीकी विशेषज्ञों और व्यवहार में काम करने वालों ने मास्टर सीआरपी की जमीनी संसाधन व्यक्ति के रूप में क्षमता बढ़ाई। वे ग्रामीण परिवारों को सहयोग देंगे और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत पशुधन आधारित आजीविका के अवसर बढ़ाएँगे।

कार्यक्रम एनआरएलएमआरसी के प्रोफेसर और स्कूल प्रमुख डॉ. रवींद्र गावली के मार्गदर्शन में हुआ। इससे सामुदायिक क्षमता, टिकाऊ पशुपालन और ग्रामीण परिवारों की आजीविका के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एसएचजी उत्पादों के निर्यात विपणन पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी



एसएचजी उत्पादों के निर्यात विपणन पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण के प्रतिभागियों और संसाधन व्यक्तियों का समूह चित्र

लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का विपणन चुनौती है। अधिकतर समूह स्थानीय बाजारों या सरस मेलों पर निर्भर हैं और उत्पादन का पैमाना बढ़ाने या वैश्विक बाजार तलाशने पर सीमित ध्यान देते हैं। इसके लिए दिल्ली शाखा के ग्रामीण उत्पाद विपणन व संवर्धन और उद्यमिता विकास केंद्र (सीएमपीआरपीईडी) ने 3 से 7 अगस्त 2026 तक एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी में एसएचजी उत्पादों के निर्यात विपणन पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया। असम, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के एसआरएलएम अधिकारियों व संभावनाशील एसएचजी तथा उत्तर प्रदेश एसआरएलएम के लिए प्रशिक्षण बनाया गया। प्रतिभागी अपने क्षेत्रों के एसएचजी और उत्पादक समूहों को निर्यात विपणन में मार्गदर्शन देंगे।

उद्देश्य ऐसे मास्टर प्रशिक्षक तैयार करना था जो अपने क्षेत्रों में एसएचजी सदस्यों को निर्यात विपणन की जानकारी और कौशल दें। वैश्विक बाजार तक पहुँच की व्यावहारिक समझ से समूह स्थानीय बाजारों के बाहर जा सकेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

पाँच राज्यों से 27 प्रतिभागी पाँच दिवसीय आवासीय कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने निर्यात बाजार व खरीदार की जरूरतें, निर्यात दस्तावेज और अनुपालन, बाजार पहुँच, डिजिटल विपणन, मूल्य शृंखला, माल ढुलाई और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, उत्पाद गुणवत्ता, बिक्री संवाद और खरीदार व्यवहार पर काम किया। कार्यक्रम ऐसे कुशल संसाधन व्यक्ति तैयार करने के लिए था जो एसएचजी को निर्यात के लिए तैयार करें। अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने पर समूहों की आय के अवसर और ग्रामीण आजीविका बढ़ेंगे।

दिल्ली शाखा के सीएमपीआरपीईडी के सहायक निदेशक श्री चिरंजी लाल ने स्वागत किया। एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी के सहायक प्रोफेसर श्री एम. के. श्रीवास्तव ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

इसके बाद विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों के सत्र हुए। इनमें गुवाहाटी के एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी निदेशक डॉ. टी. विजय कुमार, सहायक प्रोफेसर डॉ. एम. के. श्रीवास्तव, दिल्ली शाखा के सहायक निदेशक श्री चिरंजी लाल उपस्थित हुए।



प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा
एपीडा, गुवाहाटी



निर्यात विपणन पर संवाद सत्र में
प्रतिभागी

दिल्ली शाखा के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अधिकारी श्री सुधीर कुमार सिंह, गुवाहाटी के एपीडा के व्यवसाय विकास प्रबंधक डॉ. साजू अधिकारी, डीजीएफटी के परामर्शदाता श्री हरीश केसरी, एनआईआरडीपीआर के राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति श्री पंकज बेजबरुआ और श्री माधबानंद राय, विपणन विशेषज्ञ श्री मानस दास तथा गुवाहाटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री आदर्श अग्रवाल शामिल थे।

सत्रों के बाद प्रतिभागियों ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), गुवाहाटी का 7 अगस्त 2026 को अध्ययन दौरा किया। उन्होंने प्राधिकरण का संचालन और निर्यात की अच्छी पद्धतियाँ समझीं।

पाठ्यक्रम निदेशक श्री चिरंजी लाल ने दिल्ली शाखा के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अधिकारी श्री सुधीर कुमार सिंह और श्री सुरेश प्रसाद के सहयोग से कार्यक्रम का समन्वय किया।

सीएमपीआरपीईडी के अधिकारियों ने ऑनलाइन प्रतिक्रिया सत्र के साथ कार्यक्रम पूरा किया। प्रतिभागियों और वक्ताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।



प्रशिक्षण में प्रतिभागियों से संवाद करते
संसाधन व्यक्ति



प्रशिक्षक प्रशिक्षण में समूह अभ्यास के परिणाम प्रस्तुत करते प्रतिभागी

कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और एसएचजी की भूमिका, संरचना, दायित्व और उनके समन्वय के नीतिगत ढाँचे की साझा समझ विकसित की गई। प्रतिभागियों ने ग्राम पंचायत योजनाओं में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) और ग्राम गरीबी न्यूनीकरण योजनाएँ (वीपीआरपी) तैयार करना, प्रस्तुत करना और एकीकृत करना सीखा।

उदाहरणों के माध्यम से ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी और एसएचजी सदस्यों की आवाज मजबूत करना भी प्रमुख उद्देश्य था। प्रतिभागियों ने तय समयसीमा और जिम्मेदारियों के साथ अपने गाँवों के लिए क्रियान्वयन योग्य कार्ययोजनाएँ बनाईं।

मुख्य सत्रों में पीआरआई-एसएचजी समन्वय का स्वरूप और दायरा, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण और स्थानीय विकास में एसएचजी की भूमिका शामिल थी। प्रतिभागियों ने ग्राम पंचायत विकास योजना तथा ग्राम सभा में एसएचजी भागीदारी का महत्व और जीपीडीपी में वीपीआरपी का एकीकरण समझा। उदाहरणों से ग्राम पंचायत विकास में एसएचजी भागीदारी बढ़ाने के सफल तरीके दिखाए गए। ग्राम सभा में वीपीआरपी लागू करने, पंचायतवार कार्ययोजना बनाने और प्रतिभागियों की योजनाएँ प्रस्तुत करने के सत्र भी हुए। एनआईआरडीपीआर की कार्यक्रम निदेशक डॉ. एस. के. सत्यप्रभा, एचपीएसआईआरडी के मुख्य संकाय सदस्य (एसडब्ल्यू एवं सीडी) श्री रविंदर कुमार, एचपीएसआरएलएम की एसपीएम-एसडी सुश्री

प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया से समग्र मूल्यांकन 94 प्रतिशत रहा। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा, वक्ता, ज्ञान में वृद्धि, कौशल विकास और दृष्टिकोण में बदलाव शामिल थे। प्रतिक्रिया ने प्रशिक्षण की विषयवस्तु, पद्धति और समग्र प्रभाव के प्रति संतोष दिखाया।

एनआईआरडीपीआर के विद्यार्थियों ने परिसर स्वच्छता अभियान में भाग लिया






एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आर. रमेश के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान में भाग लेते एनआईआरडीपीआर के विद्यार्थी

स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के पीजीडीआरडीएम और पीजीडीएम (आरएम) के विद्यार्थियों ने 17 अगस्त 2026 को परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान सुबह 7 से 8 बजे तक चला और विंध्याचल छात्रावास से शुरू हुआ।

उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी बढ़ाना तथा स्वच्छ और स्वस्थ परिसर बनाए रखने में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

ग्रामीण अवसंरचना केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. आर. रमेश ने नेतृत्व किया। दोनों पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों ने उत्साह और सामूहिक जिम्मेदारी से भाग लिया।

एक घंटे में विद्यार्थियों ने परिसर के तय हिस्सों को साफ किया और कचरे के 15 थैले इकट्ठे किए। विद्यार्थियों की पहल ने परिसर की स्वच्छता और जिम्मेदार कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने में उनकी भूमिका दिखाई।

विद्यार्थियों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा। इसने स्वच्छ भारत मिशन के मूल्यों, अनुशासन, नागरिक जिम्मेदारी, टीम भावना और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत किया।

अभियान ने स्वच्छ और स्वस्थ परिसर के प्रति पीजीडीआरडीएम और पीजीडीएम (आरएम) के विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता दिखाई। सामूहिक प्रयास से एनआईआरडीपीआर में स्वच्छता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को बल मिला।

एनआईआरडीपीआर में सामुदायिक पौधरोपण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रयास







सामुदायिक पौधरोपण में प्रतिभागी, एनआईआरडीपीआर के संकाय और कर्मचारी, तथा श्री सत्य साई सेवा फाउंडेशन के स्वयंसेवक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने श्री सत्य साई सेवा फाउंडेशन, मेहदीपट्टनम समिति के सामुदायिक पौधरोपण अभियान की मेजबानी की। पर्यावरण संरक्षण के इस प्रयास में स्थानीय नागरिक, स्कूली बच्चे, संस्थान के विद्यार्थी और कर्मचारी साथ आए।

अलग-अलग पीढ़ियों ने पर्यावरण की रक्षा और देखभाल की साझा जिम्मेदारी निभाई। स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और एनआईआरडीपीआर समुदाय के साथ आने से युवा पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी।

परिसर में बेल, बादाम, कदंब, करंज, आँवला और जामरूल समेत देशज और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल वृक्षों के लगभग 30 पौधे लगाए गए। विविध प्रजातियों का चयन हरियाली बढ़ाने और स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए किया गया।

प्रतिभागियों को लगाए गए पेड़ों का पारिस्थितिक महत्व बताया गया। सीएमयू के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. रमेश शक्तिवेल, सीआरआई के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. आर. रमेश, सहायक कुलसचिव डॉ. पी. के. घोष, सीपीएमई के सहायक प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. प्रभाकर और संस्थान के कर्मचारी श्री श्यामला राव ने देशज प्रजातियों के महत्व और पौधों की निरंतर देखभाल व सुरक्षा पर विचार साझा किए।

प्रतिभागियों ने स्वयं पौधे लगाए और अलग-अलग पौधों की जिम्मेदारी ली। इससे पौधरोपण सामूहिक पर्यावरणीय प्रयास बना और लोगों ने रोपण के दिन के बाद भी पौधों की देखभाल का दायित्व लिया।

कार्यक्रम ने दिखाया कि सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत सहयोग से पर्यावरण की देखभाल कैसे आगे बढ़ सकती है।

एक वृक्ष का मूल्य

1979 का अनुमान और 2011–12 का संशोधित मूल्य

क्र. सं.	पारिस्थितिकी तंत्र की सेवा या योगदान	1979 में अनुमानित लागत (अमेरिकी डॉलर)	2011–12 में संशोधित लागत (अमेरिकी डॉलर)	2011–12 में मूल्य (भारतीय रुपये)
1	ऑक्सीजन का उत्पादन	31,250	10,500	9,97,500
2	पशुओं के मांस और हड्डियों के निर्माण में योगदान	3,000	3,000	2,85,000
3	मृदा अपरदन पर नियंत्रण और मिट्टी की उर्वरता	31,250	10,000	9,50,000
4	जल का पुनर्चक्रण, आर्द्रता और हवा के तापमान का नियंत्रण	37,500	1,54,560	1,46,83,200
5	पक्षियों, गिलहरियों और कीटों को आश्रय, पारिस्थितिकी को लाभ	31,250	1,29,700	1,23,21,500
6	हवा से निलंबित कण (एसपीएम), कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि हटाना	62,000	4,02,000	3,81,90,000
	कुल	**1,96,250**	**7,09,760**	**6,74,27,200**

टिप्पणी — रुपये में मूल्य 10 सितंबर 2026 की दर ₹95 प्रति अमेरिकी डॉलर से दोबारा निकाले गए हैं।

स्रोत — मूल तालिका से अनुकूलित।



सामुदायिक पौधरोपण में प्रतिभागी, एनआईआरडीपीआर के संकाय और कर्मचारी, तथा श्री सत्य साई सेवा फाउंडेशन के स्वयंसेवक

खंड विकास अधिकारियों के लिए एनआईआरडीपीआर का क्षमता निर्माण कार्यक्रम



ग्रामीण अवसंरचना केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. आर. रमेश, बीडीओ क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 3–8 अगस्त 2026 को खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के लिए 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शत-प्रतिशत कवरेज और समृद्ध खंडों का निर्माण' पर छह दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

खंड स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नेतृत्व, योजना, प्रबंधन और शासन की क्षमताएँ बढ़ाना उद्देश्य था। कार्यक्रमों के समन्वय, शत-प्रतिशत कवरेज, साक्ष्य-आधारित योजना, जलवायु सहनशीलता, डिजिटल शासन और टिकाऊ आजीविका पर जोर रहा।

बीडीओ के नेतृत्व को मजबूती

कार्यक्रम में बीडीओ को प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण बदलाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार करने पर जोर रहा। सत्रों में परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्रामीण विकास योजना, वित्तीय प्रबंधन, संसाधन जुटाना, जलवायु सहनशीलता, समुदाय आधारित आजीविका, डिजिटल शासन और प्रौद्योगिकी शामिल थे।

प्रतिभागियों ने जीआईएस आधारित योजना के लिए 'युक्तधारा' पोर्टल का अभ्यास किया। इससे प्रौद्योगिकी और साक्ष्य के आधार पर फैसले लेने की समझ बढ़ी।

अभ्यास से सीख

संवाद, प्रकरण अध्ययन, भूमिका-अभिनय, समूह अभ्यास, प्रस्तुतियों और कार्ययोजना के माध्यम से सहभागी और अनुभव आधारित सीख हुई। मैदानी दौरे ने कक्षा के अध्ययन को जमीनी परिस्थितियों से जोड़ा।

प्रतिभागियों ने जमीनी चुनौतियों पर विचार किया और अपने खंडों में लागू करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजनाएँ तैयार कीं।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत सामाजिक समावेशन को गति देने पर राष्ट्रीय कार्यशाला



डीएवाई-एनआरएलएम के तहत सामाजिक समावेशन को गति देने पर राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागी और गणमान्य अतिथि

सामाजिक समावेशन को मिशन की प्रमुख प्राथमिकता बनाना

राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एनआईआरडीपीआर के संसाधन प्रकोष्ठ के सहयोग से चार दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला 17 से 20 अगस्त 2026 को हैदराबाद के एनआईआरडीपीआर में एस. के. राव सम्मेलन कक्ष में हुई। 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 68 प्रतिभागियों के साथ एनएमएमयू व एनआईआरडीपीआर के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति और नागरिक समाज संगठन शामिल हुए।

डीएवाई-एनआरएलएम का सामाजिक समावेशन (एसआई) विषय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), दिव्यांग व्यक्तियों, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य बहिष्कृत समूहों को आजीविका, पात्र लाभ और संस्थागत भागीदारी तक सार्थक पहुँच दिलाता है। राज्यों में क्रियान्वयन असमान होने के कारण कार्यशाला का उद्देश्य सामाजिक समावेशन को फिर से प्रमुख प्राथमिकता बनाना और एसआरएलएम को शुरुआती आकलन से आगे बढ़ाकर स्थानीय जरूरतों के अनुकूल कार्रवाई तक ले जाना था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अमित शुक्ला, आईएफएस, ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को समूहों से जोड़ने के साथ ऐसा समावेशन बढ़ाने पर बल दिया जो जीवन में बदलाव लाए, मुश्किलों से निपटने की क्षमता बढ़ाए और वंचित समुदायों को सम्मान, समान भागीदारी, अवसर और नेतृत्व दे। एनआईआरडीपीआर के डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ के प्रोफेसर एवं स्कूल प्रमुख डॉ. रवींद्र एस. गावली ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्पष्ट रणनीतियों और समन्वय के लिए मजबूत सामुदायिक संस्थाओं की जरूरत बताई। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एनएमएमयू के राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक (एसआई) श्री ओम प्रकाश और संसाधन प्रकोष्ठ के उप परियोजना निदेशक डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती ने साझा सीख, व्यवस्थित पद्धतियों और अमल योग्य योजना पर जोर दिया।

पहले दिन छह सत्रों में समावेशन की अवधारणाएँ, ढाँचे और मैदान में परखे गए मॉडल प्रस्तुत किए गए।



सामाजिक समावेशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन

डीएवाई-एनआरएलएम



सामाजिक समावेशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन

डीएवाई-एनआरएलएम

श्री डी. राजेश्वर और श्री जी. भार्गव ने 'अपनत्व का मार्ग' प्रस्तुत किया, जो वंचित समूहों की उपस्थिति से आगे बढ़कर सार्थक समावेशन पर जोर देता है। श्रीमती दीपा राजकमल और श्री डी. राजेश्वर ने कमजोर समूहों की सहनशीलता बढ़ाने का सप्तसूत्र ढाँचा बताया। श्री जी. भार्गव ने समग्र योजना के लिए जीवन-निर्वाह-वृद्धि-विकास (एस-जी-डी) ढाँचा प्रस्तुत किया। एल्डर्स फॉर एल्डर्स फाउंडेशन (ईएफईएफ) के श्री एलांगो ने बुजुर्गों का बड़ा संघ बनाने का अनुभव साझा किया। श्री अकबर महफूज आलम ने साइटसेवर्स इंडिया का दिव्यांग समावेशन और आजीविका मॉडल बताया। सहोदरी फाउंडेशन की सुश्री कल्कि सुब्रमण्यम ने शिक्षा, आजीविका और अधिकारों की पैरवी के जरिये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और निराश्रित महिलाओं के सशक्तीकरण के 18 वर्षों के काम का उल्लेख किया। इसमें एनआईआरडीपीआर के साथ विकसित ट्रांस उद्यमिता कार्यक्रम और 'कोकोफ्रेंड्स' कारीगर पहल शामिल हैं।

दूसरे दिन तेलंगाना के नागरकर्नूल, रंगारेड्डी और यादाद्री जिलों में पीवीटीजी, दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के साथ काम करने वाले एसएचजी का दौरा हुआ। इससे संवेदनशीलता, अपनत्व और समन्वय की कक्षा चर्चाएँ जमीन से जुड़ीं।

तीसरे दिन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और सहयोगी संगठनों ने मैदान में परखे मॉडल साझा किए।

मध्य प्रदेश के प्रदान ने पीवीटीजी समुदायों के साथ पुनर्योजी कृषि और सौर सिंचाई का अनुभव साझा किया। टीएनएसआरएलएम ने दिव्यांग व्यक्तियों को एसएचजी से जोड़ने और दिव्यांग उद्यमियों की सफलता बताई। बिहार की बीआरएलपीएस (जीविका) ने वरिष्ठ नागरिक स्वयं सहायता समूह की पहल बताई। झारखंड की जेएसएलपीएस ने पीवीटीजी परिवारों की रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच में सुधार दिखाया। अंत में श्री जी. भार्गव और श्रीमती दीपा राजकमल ने एस-जी-डी दृष्टिकोण के लिए कमजोरियों की सहभागी, सम्मानजनक और गोपनीय पहचान का मैदानी उपकरण प्रस्तुत किया।

अंतिम दिन राज्यवार समूहों ने सामाजिक समावेशन की तीन वर्षीय परिकल्पना बनाई। असम, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ने इन्हें साझा किया। एनएमएमयू के राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक (एसआई) श्री ओम प्रकाश ने समीक्षा की।

आलेख तैयार किया: राजीव रंजन सिंह, मिशन कार्यपालक-एसआईएसडी,
डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ

सामाजिक जवाबदेही और सामाजिक अंकेक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण सामग्री पर लेखन कार्यशाला



डॉ. एस. ज्योतिस, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीजीएस एवं डीई; डॉ. सी. धीरजा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, सामाजिक अंकेक्षण केंद्र; और डॉ. श्रीनिवास सज्जा, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक अंकेक्षण केंद्र, लेखन कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ

एनआईआरडीपीआर के सामाजिक अंकेक्षण केंद्र ने सामाजिक जवाबदेही और सामाजिक अंकेक्षण के एक माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए 6–7 अगस्त 2026 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में दो दिवसीय लेखन कार्यशाला आयोजित की।

विशेषज्ञों और क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर मिलकर विचार किया। उन्होंने पाठ्यक्रम की संरचना, प्रमुख विषयों, सामग्री में सुधार और सीखने के उपयुक्त घटक तय करने पर काम किया, ताकि कार्यक्रम व्यापक, व्यावहारिक और हितधारकों की जरूरतों के अनुरूप हो।

प्रतिभागियों ने अवधारणाओं को व्यावहारिक ज्ञान और मैदानी अनुभव से जोड़ने के तरीकों पर विचार किया, ताकि शिक्षार्थी सामाजिक जवाबदेही की व्यवस्थाओं और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रियाओं को बेहतर समझ सकें। प्रशिक्षण सामग्री को स्पष्ट सीखने के उद्देश्यों पर आधारित रखने और क्षमता निर्माण का प्रभावी ढाँचा बनाने पर जोर दिया गया।

प्रस्तावित एक माह का पाठ्यक्रम सामाजिक जवाबदेही और अंकेक्षण से जुड़े हितधारकों का ज्ञान और कौशल बढ़ाने की पहल है। सहभागी प्रक्रियाओं और जवाबदेही तंत्र की गहरी समझ से ग्रामीण विकास और शासन में पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और जवाबदेही बढ़ाने का लक्ष्य है।

कार्यशाला ने ऐसे व्यवस्थित और व्यवहार आधारित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के विकास को आगे बढ़ाया जो सामाजिक जवाबदेही और अंकेक्षण की पद्धतियों को संस्थागत रूप दे सके।

बंद करघे से जीवंत विरासत तक
कुणबी साड़ी के पुनरुद्धार से नई आजीविकाएँ
शिरोडा, गोवा

श्री रवि नायडू,
एमई-आईबीसीबी, एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ
एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद



शिरोडा के हथकरघा केंद्र में जीएसआरएलएम और एनआरएलएम की टीम, जहाँ स्थानीय स्वयं सहायता समूह की कारीगर कुणबी साड़ियाँ बुनती हैं

गोवा के अंदरूनी हिस्से में बसे शिरोडा की बस्तियों में थोड़ी दूर चलने पर एक आवाज सुनाई देती है जो भारत के अधिकतर गाँवों से लगभग गायब हो चुकी है, हथकरघे की लयबद्ध खटखट। साधारण दरवाजों के पीछे महिलाएँ लकड़ी के करघों पर धागे की नाव आगे-पीछे करके लाल चौखानेदार कुणबी साड़ी बुनती हैं। कभी इसे केवल गोवा की जनजातीय महिलाएँ पहनती थीं। अब इसे गोवा की सांस्कृतिक पहचान के रूप में फिर देखा जा रहा है। इन केंद्रों में गोवा के ग्रामीण विकास की उल्लेखनीय कहानी दिखती है, राज्य की सबसे पुरानी हथकरघा सहकारी संस्था, शिरोडा हथकरघा औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड का पुनरुद्धार।

1987 में बनी और लगभग खो गई सहकारी संस्था

शिरोडा हथकरघा औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना 1987 में माननीय विधायक श्री सुभाष शिरोडकर के मार्गदर्शन में हुई। उद्देश्य पारंपरिक हथकरघा बुनाई बढ़ाना और महिला कारीगरों को आजीविका देना था। शुरुआती वर्षों में कुछ महिलाओं को बुनाई सिखाई गई और शिरोडा के आनंदवाड़ी में हथकरघा केंद्र खुला। सस्ते पावरलूम उत्पादों से प्रतिस्पर्धा और गोवा में सीमित माँग से उत्पादन धीरे-धीरे बंद हो गया। कई वर्षों तक समिति मुख्यतः कागज पर रही।

2021 में सरकार की पहल से कुणबी साड़ी की वापसी

बदलाव 2021 में आया, जब गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कुणबी साड़ी को बचाने और पुनर्जीवित करने की राज्यस्तरीय पहल शुरू की। यह हाथ से बुना वस्त्र ऐतिहासिक रूप से गोवा के जनजातीय समुदायों से जुड़ा था। बदलती जीवनशैली और घटते उत्पादन से इसके लुप्त होने का

खतरा था। पुनरुद्धार की रणनीति के तहत महिलाओं, खासकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को बुनाई का प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग दिया गया।

शिरोडा समिति ने स्थानीय स्तर पर पहल सँभाली। गोवा सरकार के हस्तशिल्प विभाग की मदद से शिरोडा की 100 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण मिला। अधिकतर एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूहों की सदस्य थीं। पहला बैच 2 अक्टूबर 2022 को शिरोडा के पाजवाड़ा में शुरू हुआ और फिर आसपास के गाँवों में कई कार्यक्रम हुए।

"केवल हथकरघा बुनाई से एक कारीगर प्रति माह लगभग ₹5,000 से ₹15,000 कमा सकती है।"



साइकिल के पहिए से बना चरखा बुनाई से पहले रीलों पर धागा लपेटने के लिए



ताना ड्रम, जिस पर साड़ी की लंबाई और के अनुसार धागे लगाए जाते हैं

हर साड़ी के पीछे बुनाई के औजार

बुनाई से पहले धागा लपेटना, नापना और करघे की बीम पर कसना पड़ता है। शिरोडा के केंद्रों में इसके लिए स्थानीय तौर पर बदले गए औजार काम आते हैं। साइकिल के पहिए से बने चरखे पर धागा रीलों पर लपेटा जाता है। बड़े लकड़ी के ताना ड्रम पर साड़ी की तय चौड़ाई और डिजाइन के अनुसार धागे लगाए जाते हैं। करघे की नाव चलने से काफी पहले यह धैर्यपूर्ण तैयारी होती है।

सात केंद्रों में छिहत्तर सक्रिय कारीगर

प्रशिक्षण से उत्पादन का नेटवर्क बना। समिति के सात हथकरघा केंद्र शिरोडा, बेथोरा और पंचवाड़ी में हैं। कुल 100 से अधिक प्रशिक्षित महिलाओं में से करीब 76 नियमित बुनाई कर रही हैं। तीन और केंद्रों के प्रस्ताव हस्तशिल्प विभाग के विचाराधीन हैं। मंजूरी मिलने पर कुल करीब दस केंद्र होंगे और क्षेत्र में रोजगार और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।

करघा कैसे आजीविका बनता है

समिति की कार्यप्रणाली सरल और चक्रीय है। हर केंद्र का प्रभारी कारीगरों के काम का समन्वय करता है। हर महीने प्रभारी उत्पादन और प्रगति की समीक्षा करते हैं तथा महीने के तैयार माल के साथ रिपोर्ट देते हैं। समिति



चौखानेदार कुणबी वस्त्र बुनती कारीगर
शिरोडा संकुल के सात सक्रिय हथकरघा केंद्रों में से एक में



करघे पर साथ काम करती दो कारीगर कुणबी कपड़े के नए थान का बाना लगाते हुए

कारीगरों से सीधे तैयार उत्पाद लेती है और अगले महीने की बुनाई के लिए धागा और अन्य कच्चा माल देती है। कारीगरों को मुख्यतः श्रम और बुनाई का भुगतान मिलता है। इससे उन्हें नियमित और प्रत्यक्ष आय होती है।

सहयोगी संस्था अस्तुरी एमसीएलएफ

2024 में अस्तुरी मॉडल संकुल स्तरीय संघ (अस्तुरी एमसीएलएफ) की अध्यक्ष डॉ. गौरी शिरोडकर हथकरघा समिति की भी अध्यक्ष चुनी गईं। दोनों संस्थाएँ मिलकर काम करती हैं। अस्तुरी एमसीएलएफ ब्रांडिंग, प्रचार और बाजार से जोड़ने में मदद करता है। इससे हथकरघा गतिविधि एनआरएलएम के व्यापक स्वयं सहायता समूह नेटवर्क से जुड़ी और प्रदर्शनियों तथा विभागीय कार्यक्रमों में उत्पाद दिखाने और बेचने के अवसर बढ़े।

आगे की प्राथमिकताएँ

समिति ने पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने के लिए ये प्राथमिकताएँ तय की हैं।

- ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन में पेशेवर परामर्श।
- उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक और जरूरत के अनुरूप हथकरघा उत्पाद।
- प्रदर्शनियों, सरकारी विभागों, निजी संगठनों और संस्थागत खरीदारों से बाजार संपर्क।
- कुणबी साड़ी और अन्य हथकरघा उत्पादों को गोवा के उत्कृष्ट विरासत उत्पाद के रूप में स्थापित करना।
- उत्पादन केंद्र बढ़ाना और अधिक महिला कारीगरों को जोड़ना।
- एनआरएलएम के एसएचजी और आजीविका पहलों से गहरा जुड़ाव।
- ऑनलाइन और व्यापक बाजारों में बिक्री की संभावनाएँ तलाशना।

फिर से बुनी गई एक कला

शिरोडा की हथकरघा समिति की कहानी ग्रामीण आजीविका के पुनरुद्धार की भी कहानी है। एक बंद संस्था को सरकार की लक्षित पहल और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से फिर काम मिला। कला और आत्मविश्वास धीरे-धीरे लौटे। गोवा की सबसे पुरानी हथकरघा सहकारी समिति अब उत्पादन केंद्रों का बढ़ता नेटवर्क है, जिसे मुख्यतः एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूह चलाते हैं। करीब दस केंद्रों तक प्रस्तावित विस्तार, पेशेवर ब्रांडिंग और अस्तुरी एमसीएलएफ के जरिये बढ़ते बाजार से कुणबी साड़ी गोवा की विरासत भी सँजो रही है और इसे बुनने वाली महिलाओं को व्यावसायिक आजीविका भी दे रही है।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहतमहिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के वित्तपोषण को बढ़ावा

सुश्री वाई. अतान कोन्याक, मिशन कार्यपालक,
एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ
एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी



मिजोरम ग्रामीण बैंक (एमआरबी) के साथ पहली बैठक।
बाईं ओर एनआरपी तिलक दास और दाईं ओर बैंक अधिकारी



11 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय बैंक अभिमुखीकरण

डीएवाई-एनआरएलएम के एसएचजी-बैंक संपर्क मॉडल के जरिए ग्रामीण महिलाओं तक संस्थागत वित्त पहुँचा और बचत, ऋण व सामूहिक कार्रवाई संभव हुई। एसएचजी ने उपभोग और बुनियादी ऋण की जरूरतें पूरी की हैं। टिकाऊ आजीविका के लिए अब उद्यम विकास में सहयोग चाहिए। उद्यमिता की ओर बढ़ रही महिलाओं के सामने ऋण इतिहास, जमानत और वित्तीय दस्तावेजों की कमी तथा अनौपचारिक उद्यमों को ऋण देने में बैंकों की हिचक जैसी बाधाएँ हैं।

इसके लिए डीएवाई-एनआरएलएम ने महिला उद्यम वित्तपोषण की पहल शुरू की। एनआईआरडीपीआर का एनआरएलएमआरसी विभिन्न राज्यों में एसआरएलएम कर्मियों की क्षमता बढ़ाकर इसमें सहयोग दे रहा है।
वित्तीय वर्ष 2026-2027 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन व्यक्तिगत उद्यम ऋण आवेदन (आईईएलए) मंच शुरू किया। यह डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप उद्यम वित्तपोषण को सरल, कुशल और जवाबदेह बनाता है।

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी के एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ ने एसआरएलएम की मदद के लिए राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति (एनआरपी) तैनात किए, राज्य स्तरीय बैंक अभिमुखीकरण और रणनीतिक योजना के लिए एसआरएलएम व बैंकों के साथ अनुवर्ती बैठकें की जा सकें।

अगस्त 2026 में मेघालय और मिजोरम में कार्यक्रम हुए। मिजोरम ग्रामीण बैंक (एमआरबी) आईईएलए मंच से जुड़ा। वह इससे जुड़ने वाला देश का पहला एसबीआई प्रायोजित ग्रामीण बैंक बना। इससे दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बना और वित्तीय समावेशन में डिजिटल मंचों की क्षमता दिखी।

मेघालय ग्रामीण बैंक ने प्रक्रिया समझ ली है। मंच से औपचारिक जुड़ाव अभी बाकी है। एनआरपी ने मेघालय ग्रामीण बैंक और मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसाइटी (एमएसआरएलएस) के बीच संवाद कराया। सहमति हुई कि आईईएलए से पूरी तरह जुड़ने से पहले भी बैंक सोसाइटी की सदस्यों के व्यक्तिगत ऋण आवेदन स्वीकार करेगा।

इन पहलों से एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ और एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी ने नीति को व्यवहार से जोड़ा, वित्तीय संपर्क में नवाचार बढ़ाया और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण उद्यमिता सहयोग को बड़े पैमाने पर लागू करने का आधार रखा।

रुचि से समृद्धि तक सुमे शर्मा का सफर गृहिणी से लखपति दीदी तक

स्वयं सहायता समूह, पारंपरिक कौशल और एएसआरएलएम के सहयोग से एक ग्रामीण महिला ने सांस्कृतिक विरासत सँजोते हुए सफल उद्यम बनाया

सुश्री संगीता आर. बरठाकुर, मिशन प्रबंधक,
एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ
एनआईआरडीपीआर–एनईआरसी, गुवाहाटी

2015 में सुमे शर्मा ने उद्यम की शुरुआत दो ऐसे हुनरों से की जो उन्हें प्रिय थे, मोमबत्ती बनाना और पारंपरिक मणिपुरी हथकरघा बुनाई। उनकी निजी रुचि धीरे-धीरे टिकाऊ आजीविका बनी और परिवार की आर्थिक स्थिति में उनका महत्वपूर्ण योगदान हुआ।

श्रीभूमि की गृहिणी सुमे के जीवन में बदलाव ने तब गति पकड़ी जब वे 2018 में नवपल्लव स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ीं। समूह से प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और ऐसे अवसर मिले जिनसे उनके हुनर ने उद्यम का रूप लिया।

हुनर से उद्यम तक

पिडिलाइट के प्रशिक्षण से सुमे ने मोमबत्ती बनाने का कौशल बढ़ाया और अपनी माँ से पारंपरिक मणिपुरी हथकरघा बुनाई सीखी। पूँजी और बाजार तक पहुँच अब भी चुनौती थी।

असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एएसआरएलएम) के सहयोग से उन्होंने ये बाधाएँ पार कीं। परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि से वित्तीय सहायता तथा क्षमता निर्माण और तकनीकी प्रशिक्षण मिलने पर उन्होंने बुनाई की मशीनें खरीदीं, कच्चा माल जुटाया और उत्पादों की गुणवत्ता सुधारी।

कनकलता महिला सबलीकरण योजना (केएएमएस) से उन्हें ₹25,000 मिले। बाद में



₹1.50 लाख का ऋण लिया, जिससे उद्यम को धीरे-धीरे बढ़ाने की पूँजी मिली।

टिकाऊ आजीविका का निर्माण

बेहतर कौशल, उपकरण और वित्त से सुमे ने हाथ से बनी मोमबत्तियों और पारंपरिक मणिपुरी हथकरघा उत्पादों की शृंखला बढ़ाई। स्थानीय बाजारों तथा दुर्गापूजा और दिवाली जैसे त्योहारों में उनकी बिक्री होती है। उत्पाद बराक घाटी और उसके बाहर भी पहुँचते हैं।

उद्यम से अब सालाना लगभग ₹2.25 लाख की आय होती है। उन्हें 'लखपति दीदी' की पहचान मिली है।
सुमे के लिए इस उपलब्धि का अर्थ आय से आगे है। यह आत्मविश्वास, स्वावलंबन और अपने हुनर व संकल्प से अवसर बनाने की क्षमता का प्रतीक है।

"लखपति दीदी बनना बताता है कि कौशल, वित्त और समुदाय का साथ मिलने पर महिलाएँ क्या हासिल कर सकती हैं।"





घरों में रोशनी और विरासत का संरक्षण

सुमे उद्यम आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण को जोड़ता है। उनकी मोमबत्तियाँ बाजार में नए उत्पाद लाती हैं और हथकरघा बुनाई पारंपरिक मणिपुरी शिल्प को जीवित रखती है।

उन्होंने मौसम की माँग और त्योहारों के अनुसार उत्पादन और विपणन बदलना सीखा। वे उद्यम बढ़ाकर दुल्लभछड़ा बाजार में दुकान खोलना चाहती हैं, ताकि अधिक ग्राहक उन तक पहुँच सकें।

अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा

गरीबी में रह रही एक गृहिणी से आर्थिक रूप से स्वतंत्र उद्यमी बनने का सुमे का सफर स्वयं सहायता समूहों और समुदाय आधारित आजीविका पहलों की बदलाव लाने की क्षमता दिखाता है।

उनकी कहानी दिखाती है कि कौशल, वित्त, संस्थागत सहयोग, तकनीक और बाजार मिलने से ग्रामीण महिलाएँ गुजारे भर की आय से आगे बढ़कर टिकाऊ उद्यम बना सकती हैं।

सुमे परिवार की आर्थिक सुरक्षा मजबूत कर रही हैं और अपने समुदाय की अन्य महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। उनकी यात्रा का संदेश है

अवसर, संसाधन और आत्मविश्वास मिलने पर महिलाएँ अपने सपनों को साकार कर सकती हैं और अपने परिवारों तथा समुदायों के जीवन में बदलाव ला सकती हैं।

यह लेख सुश्री नीतू दास से मिली जानकारी पर आधारित है।
डीएफई-एसएमआईबीसीबी, श्रीभूमि

एनआईआरडीपीआर ने 80वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया








राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 15 अगस्त 2026 को भारत का 80वाँ स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया। संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय गौरव और देश के विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भाग लिया।

एनआईआरडीपीआर की उप महानिदेशक सुश्री रोहिणी आर. भाजिभाकरे, आईएएस, की अनुपस्थिति में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र (सीपीजीएस एवं डीई) के प्रोफेसर एवं प्रमुख प्रो. ज्योतिस सत्यपालन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

विकसित भारत 2047 की ओर

एनआईआरडीपीआर समुदाय को सहयोग, पेशेवर निष्ठा, समर्पण और उत्साह से काम करने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि संस्थान अधिक आत्मनिर्भर बने और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मजबूत हो।

संदेश में विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय परिकल्पना में एनआईआरडीपीआर का निरंतर योगदान रेखांकित किया गया। विशेष बल क्षमता निर्माण, ज्ञान सृजन और प्रसार तथा ग्रामीण विकास पहलों को सहयोग देने पर रहा।

स्वतंत्रता दिवस पर एनआईआरडीपीआर समुदाय ने ग्रामीण बदलाव, संस्थागत उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई। अधिक समावेशी और समृद्ध भारत की यात्रा से प्रेरणा ली गई।

अकेले नेतृत्व कर बदलाव लाने वाली ग्राम प्रधान शोभा देवी

एक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के संघर्ष, सेवा और नेतृत्व की कहानी उत्तराखंड के एक पहाड़ी गाँव से

इंजी. एच. के. सोलंकी,
वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, सीएनआरएम, सीसी एवं डीएम, एनआईआरडीपीआर
hksolanki@nird.gov.in



शोभा देवी ग्राम पंचायत के खाते और अभिलेख स्वयं रखती हैं।

स्रोत — पद्म पुरस्कार नामांकन दस्तावेज, निजी संग्रह

ग्राम प्रधान शोभा देवी, ग्राम पंचायत जुड़ल्यु (नैनीडांडा खंड, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड) की कहानी दूरदराज के पहाड़ी गाँवों में विकास का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के लिए उदाहरण है। वे परिवार, पशुपालन और खेती का पूरा भार भी उठाती हैं। परिवार की आजीविका के लिए उनके पति काम की तलाश में मुंबई गए हैं। गाँव में उनकी अनुपस्थिति में उनके नैतिक समर्थन के सहारे शोभा देवी पंचायत का काम स्वयं चलाती हैं। उनका अनुभव दिखाता है कि इच्छाशक्ति और मनोबल से सीमित संसाधनों में भी बदलाव संभव है।

सपने टूटे, संकल्प बना रहा

बचपन में शोभा देवी आगे पढ़कर भारतीय सेना में जाना चाहती थीं। परिवार की आर्थिक सीमाओं के कारण आसपास की अन्य लड़कियों की तरह वे दसवीं तक ही पढ़ सकीं। गरीबी, सामाजिक दबाव और परंपरा के चलते कम उम्र में उनका विवाह हुआ और आगे की पढ़ाई व सेना में जाने का सपना अधूरा रह गया। आज उनके काम और क्षमता को देखकर माता-पिता को कम उम्र में विवाह करने और आगे न पढ़ाने का पछतावा है।

पति का नैतिक समर्थन और स्वयं नेतृत्व

शोभा देवी के दो बेटे पढ़ाई के लिए घर से दूर रहते हैं और पति परिवार की आर्थिक मदद के लिए मुंबई में काम करते हैं। शोभा देवी के अनुसार पति उनका पूरा मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने समाज के लिए काम करने की स्वतंत्रता और साहस दिया। गाँव से दूर होने के कारण वे घर या पंचायत का काम सीधे नहीं बाँट पाते। घर, सास की देखभाल, गाय-बकरियाँ, छोटे और बिखरे खेत तथा पंचायत का काम शोभा देवी अकेले संभालती हैं। वे ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी अपने विवेक से और किसी दबाव के बिना निभाती हैं। पुरुष प्रधान सामाजिक ढाँचे में महिला प्रतिनिधि के रूप में रोज नई कठिनाइयाँ आती हैं, फिर भी वे पीछे नहीं हटतीं। वे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के स्वयं सहायता समूह

की पशु सखी भी हैं। वे गाँव के मंगल समूह का नेतृत्व करती हैं और समूह की जमा राशि से जरूरतमंद और बीमार लोगों के इलाज की व्यवस्था करती हैं।

पंचायत के विकास कार्य

शोभा देवी के नेतृत्व में पंचायत ने पौधरोपण, इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण, भूमि समतलीकरण और सौर बत्तियाँ लगाने जैसे काम किए। जल जीवन मिशन के तहत संबंधित विभागों के सहयोग से गाँव की पेयजल आपूर्ति सुधारी गई। पंचायत का मामला हो या किसी दूसरे विभाग का, वे लोगों की मदद के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे संपर्क करती हैं। पंचायत के काम और खातों की वे स्वयं पारदर्शी ढंग से निगरानी करती हैं। गाँव के निरक्षर, असहाय और बुजुर्ग लोग हर तरह की समस्या लेकर उनके पास आते हैं।

वन्यजीव संघर्ष से जलवायु परिवर्तन तक शोभा देवी की चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन भी मनुष्यों और वन्यजीवों का संघर्ष बढ़ा रहा है। बाघ पालतू कुत्तों, गायों और बकरियों को उठा ले जाते हैं। इससे पशुधन पर निर्भर आजीविका खतरे में रहती है। जंगली सूअर खड़ी फसल और बंदर फलदार पेड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। पहाड़ी इलाके में छोटी और बिखरी जोतों के कारण खेती कठिन है। अतिवृष्टि, सूखा और मृदा अपरदन भी लगातार चुनौतियाँ हैं। शोभा देवी उपलब्ध संसाधनों के भीतर समाधान तलाशती रहती हैं।

पलायन रोकने और सामाजिक बदलाव के प्रयास

पहाड़ी गाँवों से पलायन कम करने के लिए शोभा देवी होमस्टे को बढ़ावा दे रही हैं, ताकि गाँव में रहकर आजीविका मिल सके। वे बच्चों का स्कूल छोड़ना घटाने और बेटी के जन्म को लेकर सामाजिक हीनभावना दूर करने में सक्रिय हैं। पारंपरिक जलस्रोतों के संरक्षण के लिए भी प्रयास करती हैं। वे पूरे खंड में अकेली महिला प्रतिनिधि हैं जो पति की भौतिक उपस्थिति के बिना स्वयं अपने प्रतिनिधि दायित्व निभाती हैं। काम के दौरान महिला और पुरुष श्रमिकों का समान रूप से ध्यान रखती हैं।



इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण की स्वयं निगरानी करती शोभा देवी।
स्रोत — पद्म पुरस्कार नामांकन दस्तावेज, निजी संग्रह



शोभा देवी और गाँव की महिलाएँ पौधरोपण करते हुए।
स्रोत — पद्म पुरस्कार नामांकन दस्तावेज, निजी संग्रह

प्रौद्योगिकी और सामाजिक माध्यम से संवाद

घर, पशु, परिवार और पंचायत सँभालने के साथ शोभा देवी तकनीक से जुड़ी हैं। वे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर गाँव और पंचायत की गतिविधियाँ नियमित रूप से साझा करती हैं। उनके काम की चर्चा गाँव से दूर तक होती है। स्थानीय समाचार चैनलों ने उनके काम पर रिपोर्ट और साक्षात्कार प्रसारित किए हैं। तकनीक और जमीनी काम का मेल उन्हें लोगों की पहुँच में रहने वाली जनप्रतिनिधि बनाता है।

पहचान और प्रशिक्षण की जरूरत

शोभा देवी अपने शेष चार वर्ष के कार्यकाल में हर ग्रामीण को साथ लेकर समावेशी विकास करना चाहती हैं। अपनी जिम्मेदारियाँ और प्रभावी ढंग से निभाने के लिए वे प्रशिक्षण और सीखने के अधिक अवसर चाहती हैं। उनका सफर जमीनी महिला नेतृत्व को पहचान, सहयोग और आगे बढ़ने के अवसर देने का महत्व बताता है। उनके अनुभव अन्य महिलाओं को स्थानीय शासन में आत्मविश्वास से भाग लेने की प्रेरणा देते हैं। पंचायती राज में महिलाओं का नेतृत्व समावेशी और समग्र ग्राम विकास की मजबूत नींव बन सकता है।

यह लेख शोभा देवी द्वारा पद्म पुरस्कार (2026) के लिए प्रस्तुत नामांकन दस्तावेज और इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा फेसबुक पर उनके सार्वजनिक खातों की जानकारी पर आधारित है। सभी फ़ोटो उसी नामांकन दस्तावेज से ली गई हैं।

वन के रक्षक
ओडिशा के साझा संसाधनों की रक्षा करते समुदाय

श्री क्षितिज राज
पीजीडीएम-आरएम, एनआईआरडीपीआर
kshitizraj@nirdpr.org.in





क्योंझर जिले के जंगलों से सटे गाँवों में,ओडिशा में दिन पहली रोशनी के साथ शुरू होता है। महिलाएँ टोकरियाँ लेकर जंगल में महुआ के फूल, तेंदू पत्ते, मशरूम, बाँस और औषधीय पौधे लेने जाती हैं। किसान मवेशियों को साझा चरागाहों में ले जाते हैं और बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं। इन जनजातीय परिवारों को वन भोजन, आय, औषधि, ईंधन और पीढ़ियों से चली आ रही जीवनशैली देते हैं।

पारिस्थितिक सुरक्षा फाउंडेशन (एफईएस) में इंटर्नशिप के दौरान मैंने जात्रा, गोनासिका और बागदेरी की तीन जनजातीय पंचायतों का दौरा किया। वहाँ समय बिताकर समझा कि लोगों का जीवन वन, तालाब, चरागाह और दूसरे साझा प्राकृतिक संसाधनों से कितना जुड़ा है। ये खेती, पशुधन और घरेलू जरूरतों का आधार हैं। बदलती आजीविका, कमजोर प्रबंधन और पर्यावरण क्षरण से इन पर दबाव बढ़ रहा है।

लोग पीढ़ियों से प्रकृति की रक्षा करते आए हैं। वे जानते हैं कि महुआ कब बटोरना है, कौन से औषधीय पौधे सामान्य रोगों में काम आते हैं और पवित्र उपवनों को क्यों छेड़ना नहीं चाहिए। वर्षों के अनुभव का यह ज्ञान आधुनिक संरक्षण कार्यक्रमों से बहुत पहले से इन क्षेत्रों की रक्षा करता आया है।

अब लोगों और प्रकृति का यह संबंध बनाए रखना कठिन हो रहा है।

मैदानी दौरों में मैंने देखा कि कई तालाबों में काफी गाद भर गई है, जिससे गर्मियों में पानी कम मिलता है। अतिक्रमण से कुछ चरागाह सिकुड़ गए और कुछ वनखंडों में ईंधन की लकड़ी और वनोपज का जरूरत से अधिक दोहन दिखा। खेती, पशुधन और घरेलू आय पर सीधा असर पड़ता है और कठिन मौसम में कई ग्रामीण परिवारों की असुरक्षा बढ़ती है।

साझा संसाधनों का प्रबंधन भी चुनौतीपूर्ण हुआ है। ग्राम पंचायत, वन समिति, पानी पंचायत और जैव विविधता प्रबंधन समिति के महत्वपूर्ण दायित्व हैं, लेकिन वे अक्सर सीमित समन्वय के साथ अलग-अलग काम करती हैं। ग्रामीणों से बातचीत में पता चला कि वन प्रबंधन की पारंपरिक व्यवस्थाएँ

पलायन, बदलती जीवनशैली और नई पीढ़ी की घटती भागीदारी से कमजोर हो रही हैं। लोग अब भी वनों और साझा भूमि पर निर्भर हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने वाली संस्थाएँ हर बार प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दे पातीं।

वन आधारित आजीविका की एक और चुनौती है। परिवार पूरक आय के लिए महुआ, तेंदू पत्ते, मशरूम, जंगली फल, बाँस और औषधीय पौधे जुटाते हैं। गाँव में भंडारण या प्रसंस्करण की सुविधाएँ सीमित हैं, इसलिए अधिकतर उपज संग्रह के तुरंत बाद बेचनी पड़ती है।

गाँव की एक बैठक में महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य ने बताया, "मेरा परिवार हर मौसम में काफी महुआ जुटाता है। भंडारण की ठीक जगह नहीं होने से उसी दिन बेचना पड़ता है। स्थानीय व्यापारी हमारी मजबूरी जानते हैं और बहुत कम दाम देते हैं। सुरक्षित भंडारण हो तो हम बेहतर दाम का इंतजार करके अधिक कमा सकते हैं।"

मैंने सामूहिक कार्रवाई के कई उदाहरण भी देखे। ग्रामीण नियमित पौधरोपण करते हैं, पवित्र वनखंडों की रक्षा करते हैं और ग्राम सभा में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर चर्चा करते हैं। महिला एसएचजी आजीविका गतिविधियों में अधिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। युवा जागरूकता अभियान और संरक्षण में सक्रिय हैं। उचित सहयोग और अवसर मिलने पर लोग अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए

अध्ययन में मैंने जीवन की गुणवत्ता सुधारने के कुछ व्यावहारिक उपाय देखे। इन गाँवों में महुआ संग्रह के जाल, सुखाने के चबूतरे, भंडारण और बेहतर बाजार संपर्क से वनोपज संग्राहकों की आय काफी बढ़ सकती है। कच्चा माल बेचने के बजाय स्थानीय प्रसंस्करण से परिवारों को बेहतर दाम और गाँव में रोजगार मिल सकता है।

गाँव की संस्थाओं का सहयोग मजबूत करना भी जरूरी है। ग्राम सभाएँ, पंचायतें, वन समितियाँ और स्वयं सहायता समूह तालाब बहाल करने, वन बचाने, चरागाह सुधारने और टिकाऊ आजीविका बढ़ाने की साझा योजना बना सकते हैं। विकास कार्यक्रम पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का सम्मान करें और उसे वैज्ञानिक योजना से जोड़ें, ताकि संरक्षण व्यावहारिक हो और समुदाय उसका नेतृत्व करे।

मैदानी अनुभव ने सिखाया कि वन जीवंत पारिस्थितिक तंत्र हैं। वे लाखों लोगों का जीवन सँभालते हैं और पीढ़ियों का ज्ञान, संस्कृति और परंपराएँ बचाते हैं। टिकाऊ संरक्षण तभी संभव है जब वनों पर निर्भर लोगों को उनकी रक्षा में बराबर का भागीदार माना जाए।

जात्रा, गोनासिका और बागदेरी में मैंने जाना कि ओडिशा के वनों का भविष्य पेड़ों और लोगों दोनों पर निर्भर है। ग्रामीणों पर भरोसा किया जाए, उन्हें सहयोग और निर्णय में जगह मिले तो संरक्षण से उनका जीवन भी बेहतर होता है। साझा संसाधनों की रक्षा से वन, तालाब और चरागाह बचते हैं और पीढ़ियों से उनकी देखभाल करने वालों का भविष्य सुरक्षित होता है। लोगों का ज्ञान, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयास हरित और टिकाऊ भविष्य की सबसे मजबूत नींव हैं।

एनआईआरडीपीआर में नए बैचों का स्वागत
पीजीडीआरडीएम और पीजीडीएम (आरएम)



अभिमुखीकरण में पीजीडीआरडीएम के 24वें और पीजीडीएम (आरएम) के नौवें बैच के नए विद्यार्थी, सीपीजीएस एवं डीई के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के साथ

स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र (सीपीजीएस एवं डीई),एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने पीजीडीआरडीएम के 24वें बैच (2026–2027) और पीजीडीएम (आरएम) के नौवें बैच (2026–2028) का अभिमुखीकरण आयोजित किया। ग्रामीण विकास और प्रबंधन में योगदान देने के इच्छुक नए विद्यार्थियों का औपचारिक स्वागत

नए विद्यार्थियों को एनआईआरडीपीआर के अकादमिक कार्यक्रमों, संस्थागत परिकल्पना और ग्रामीण विकास में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उसकी भूमिका से परिचित कराया गया। उन्होंने अध्ययन के माहौल, संस्थागत व्यवस्थाओं और अपने कार्यक्रमों के दौरान उपलब्ध सीखने के अवसरों को

विद्यार्थियों ने संकाय सदस्यों और कर्मचारियों से बात की तथा केंद्र के अंतर्विषयी अकादमिक और शोध परिवेश को समझा। उन्हें एनआईआरडीपीआर में मिलकर सीखने के अवसर और समकालीन ग्रामीण विकास की चुनौतियों के समाधान में अकादमिक ज्ञान को व्यवहार से जोड़ने का महत्व

संवाद सत्रों में शैक्षणिक अपेक्षाएँ, शोध के अवसर, मैदानी कार्य और अंतर्विषयी अध्ययन की जानकारी मिली। विद्यार्थियों ने अपने पाठ्यक्रमों का व्यापक दायरा समझा। उन्हें अलग-अलग दृष्टिकोणों से जुड़ने और ग्रामीण परिवर्तन में योगदान के लिए जरूरी ज्ञान, कौशल व पेशेवर क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वायत्त संगठन और ग्रामीण विकास व पंचायती राज का प्रमुख राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। यूएन-एस्कैप के उत्कृष्टता केंद्रों में मान्यता प्राप्त संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श से ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमता बढ़ाता है। संस्थान तेलंगाना के ऐतिहासिक नगर हैदराबाद में है। स्थापना की स्वर्ण जयंती 2008 में मनाई गई। मुख्य परिसर के अलावा गुवाहाटी, असम में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र, नई दिल्ली में शाखा और वैशाली, बिहार में करियर मार्गदर्शन केंद्र है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राजेंद्रनगर, हैदराबाद – 500 030
फ़ोन: (040) 24008473, फ़ैक्स: (040) 24008473
ईमेल: CDC.NIRD@GOV.IN, वेबसाइट: WWW.NIRDPR.ORG.IN

सुश्री रोहिणी आर. भाजिभाकरे, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर
सहायक संपादक: कृष्ण राज के. एस.
और अपर्णा वी. आर.

आवरण डिजाइन: वी. जी. भट्ट
प्रकाशक: ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीजीएस एवं डीई
एनआईआरडीपीआर की ओर से, राजेंद्रनगर, हैदराबाद – 500 030